पशुधन गणना: किसानों को समर्थ बनाना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना

28 अक्टूबर 2024

परिचय

भारत के समृद्ध और विविध प्रकार के पशुधन संसाधन आजीविका कमाने में लाखों लोगों की सहायता करते हुए अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पशुधन संबंधी रुझानों पर बारीकी से नजर रखना महत्वपूर्ण है। हर पांच साल में कराई जाने वाली पशुधन गणना, पशुधन की संख्या, वितरण और संरचना के संबंध में आवश्यक डेटा प्रदान करती है, चुनौतियों का समाधान करने और वहनीयता में सुधार लाने में नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करती है। यह समग्र सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कसौटी का कार्य करता है, जिससे न केवल पशुधन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति रेखांकित होती है, बल्कि भविष्य की योजना और विकास के लिए मंच भी तैयार होता है। पशुधन गणना से प्राप्त अंतर्दृष्टि सुविचारित निर्णय लेने और पूरे उद्योग में टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी और आईएसएस)[1]

पशुपालन सांख्यिकी (एएचएस) प्रभाग "पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण" योजना के माध्यम से पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राज्य पशुपालन विभागों के सहयोग से की गई यह पहल पशुधन की सांख्यिकी और रुझानों के बारे में व्यापक डेटा एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य अधिदेश:

1. पंचवर्षीय पशुधन गणना (एलसी): 1919 से हर पांच साल में आयोजित की जाने वाली पशुधन गणना का उद्देश्य पशुओं और मुर्गियों की समग्र संख्या प्रदान करना है। 20वीं गणना में डेटा संग्रह के लिए विशेष रूप से टैबलेट कंप्यूटर का उपयोग किया गया। हाल ही में, 21वीं पशुधन गणना की घोषणा की गई है।

2. वार्षिक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस): 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले सर्वेक्षण के माध्यम से दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि मार्च से फरवरी तक होती है, जिसे तीन मौसमों में विभाजित किया जाता है। इसमें "ईएलआईएसएस" सॉफ़्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (सीएपीआई) का उपयोग किया जाता है।

3. प्रकाशन:

• **अखिल भारतीय पशुधन रिपोर्ट**: यह रिपोर्ट प्रजातियों, उपयोग, लिंग और आयु के अनुसार पशुधन की तादाद का विवरण प्रदान करती है।

• **नस्ल-वार रिपोर्ट**: यह रिपोर्ट नवीनतम गणना के आधार पर विस्तृत पशुधन डेटा प्रदान करती है।

• **बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी**: यह प्रमुख पशुधन उत्पादों के लिए उत्पादन अनुमान जारी करने वाला वार्षिक प्रकाशन है।

पशुधन गणना का महत्व

भारत के पशुधन और मुर्गीपालन संसाधन व्यापक हैं और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में लगभग 303.76 मिलियन गोजातीय पशु हैं, जिनमें गाय-बैल, भैंस, मिथुन और याक शामिल हैं, साथ ही 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। ये पशुधन संसाधन केवल पोषण और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश भर में टिकाऊ कृषि पद्धतियों की सहायता करने के लिए भी आवश्यक हैं।[2]

पशुधन क्षेत्र में वृद्धि

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 31 मई 2024 को जारी अनंतिम अनुमानों से पता चलता है कि पशुधन क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर लगभग 13,55,460 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जीवीए का लगभग 30.23 प्रतिशत है। 2011-12 की स्थिर कीमतों के साथ समायोजित होने पर, जीवीए लगभग 6,90,268 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 2021-22 और 2022-23 के दौरान दूध उत्पादन क्रमशः 222.07 मिलियन टन और 230.58 मिलियन टन दर्ज किया गया, जो 3.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। यह ग्रामीण आजीविका और व्यापक अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को बढ़ाते हुए बढ़ती उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करता है।[3]

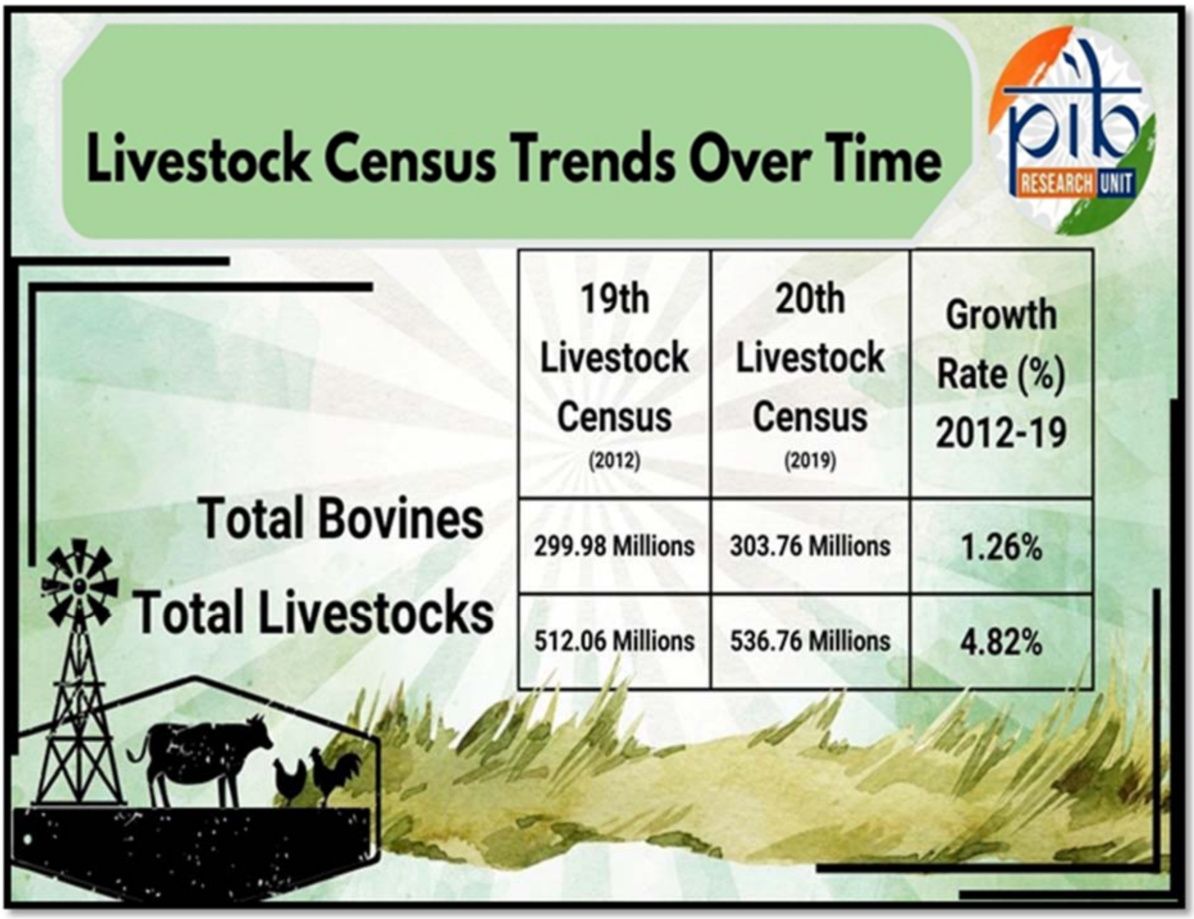

21वीं पशुधन गणना [4]

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने **25 अक्टूबर को नई दिल्ली में 21वीं पशुधन गणना** की घोषणा की। इस कार्यक्रम ने डेटा संग्रह की सटीकता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल प्रगति की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इन नवाचारों में वास्तविक समय के डेटा संग्रह के लिए एक नया मोबाइल एप्लिकेशन शामिल है, जिसे एक वेब-आधारित डैशबोर्ड द्वारा पूर्णता प्रदान की जाएगी जो निरंतर ट्रैकिंग और समय पर जानकारी संभव बनाएगा। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण गणना सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन डेटा जुटाने की क्षमताओं को शामिल किया गया है।

गणना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से अधिक फील्ड कर्मियों को प्रशिक्षित करने, साथ ही डेटा संग्रह प्रक्रिया में सहायता के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने सहित व्यापक तैयारियां की गईं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करते हुए, गणना का उद्देश्य खानाबदोश समुदायों और चरवाहों सहित भारत की पशुधन प्रथाओं की पूरी विविधता को शामिल करना है।

यह गणना मवेशी पालन में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे इस क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के बारे में व्यापक समझ प्राप्त होगी। यह पशु स्वास्थ्य, उत्पादकता और रोग नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए पशुधन नस्लों की सटीक पहचान करने हेतु इमेज-बेस्ड तकनीक का उपयोग करते हुए क्षेत्र की नस्ल प्रबंधन पर भी जोर देगी।

पशुधन की बेहतरी के लिए योजनाएं[5]

भारत के पशुधन क्षेत्र में उत्पादकता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रति लक्षित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। यहां कुछ प्रमुख पहलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): 2014 में शुरू किया गया आरजीएम दूध उत्पादन में सुधार लाने और ग्रामीण किसानों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए डेयरी फार्मिंग को लाभदायक बनाने के लिए देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ और जीनोमिक चयन के माध्यम से आनुवंशिक सुधार पर जोर देता है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): 2014-15 में शुरू किए गए एनएलएम का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास तथा मांस, अंडे, दूध और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह पशुधन क्षेत्र में

फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के लिंकेज का समर्थन करता है, ताकि असंगठित क्षेत्र का औपचारिक बाजारों के साथ एकीकरण संभव बनाया जा सके।

3. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी): इस योजना का उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम करने और अंततः उनका उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम और रोग निगरानी को लागू करके पशु स्वास्थ्य में सुधार लाना है। निधियन पैटर्न में कुछ कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता और अन्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा निधियन शामिल है।

4. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): एनपीडीडी का उद्देश्य गुणवत्ता परीक्षण और शीतलन हेतु बुनियादी ढांचे के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ दूध की गुणवत्ता में सुधार लाना और संगठित दूध खरीद को बढ़ाना है। घटक बी, एक जेआईसीए समर्थित पायलट परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में डेयरी के बुनियादी ढांचे और बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है।

5. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी): 2019 में शुरू किए गए एनएडीसीपी का उद्देश्य पशुओं को टीकाकरण करके खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना है। इसका लक्ष्य गाय-बैल, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों की आबादी का एफएमडी और मादा गोजातीय बछड़ों का ब्रुसेलोसिस के लिए 100 प्रतिशत टीकाकरण करना है।

6. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ): 2017-18 में शुरू की गई, डीआईडीएफ प्रसंस्करण और शीतलन अवसंरचना को उन्नत बनाने के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य नाबार्ड, सरकारी योगदान और अंतिम उधारकर्ताओं से वित्त पोषण के साथ दूध खरीद प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है।

7. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत एएचआईडीएफ इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा उत्पादन, नस्ल सुधार और पशु चिकित्सा टीका सुविधाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देता है।

8 डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसीएफपीओ): यह योजना डेयरी सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है, जिससे दूध उत्पादकों के लिए निरंतर संचालन और बाजार पहुंच सुनिश्चित होती है।

इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य पशुधन उत्पादकता में सुधार लाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और देश भर में पशुपालकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता करना है।

निष्कर्ष

21वीं पशुधन गणना राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी), और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)जैसी पशुधन -केंद्रित योजनाओं और पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यापक और अद्यतन डेटा प्रदान करते हुए यह गणना क्षेत्र में आवश्यकताओं और अवसरों की पहचान करने में मदद करेगी, जिससे सरकार इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इन्हें बेहतर बनाने में सक्षम हो सकेगी। एकत्रित जानकारी न केवल मौजूदा पहलों को मजबूत करेगी, बल्कि पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से नई रणनीतियों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। अंततः, यह पशुधन क्षेत्र के सतत विकास में योगदान देगी, जिससे लाखों परिवारों को लाभ होगा और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

संदर्भ

- https://dahd.gov.in/sites/default/files/202306/FINALREPORT2023ENGLISH.pdf (Page No. 4)
- https://www.dahd.gov.in/sites/default/files/2024-10/LS497.pdf
- https://www.dahd.gov.in/sites/default/files/2024-10/RS998.pdf
- https://nlm.udyamimitra.in/
- https://www.dahd.gov.in/sites/default/files/2024-10/LS2365.pdf (Graphic Data GVA Constant Prices)
- https://www.dahd.gov.in/schemes-programmes

पीडीएफ फाइल के लिए यहां देखिए

******

एमजी/आरपीएम/केसी/आरके

(Backgrounder ID: 153374)